मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

बसपा अकेले दम पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव: मायावती

- **मायावती ने कहा कि, गठबंधन करके चुनाव लड़ने से पार्टी का वोट प्रतिशत कम हो जाता है।**
- **बसपा से गठबंधन करने वाले को फायदा होता है, इसलिये अधिकांश पार्टियां बसपा से मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं।**

लखनऊ, 15 जनवरी। 'इंडिया' गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को विराम देते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि, उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव दलित, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यकों के साथ अकेले दम पर लड़ेगी।

अपने 68वें जन्मदिवस के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रैंस में मायावती ने कहा कि, गठबन्धन को लेकर पार्टी का मानना है कि, इस मामले में अभी तक का अनुभव यही रहा है कि गठबन्धन करके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बसपा से गठबन्धन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुँच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियाँ बसपा से गठबन्धन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बसपा के हित को भी देखना जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुये अब बसपा के लिए अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा।

उन्होने कहा कि, लोकसभा आमचुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी, अकेले चुनाव लड़कर, खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है, ऐसी आमधारणा है, जिसकी वजह से बसपा को भी यूपी समेत पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है।

इसके बावजूद भी, हमारी पार्टी यह सोच कर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाये तब फिर सम्बन्धित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है, हालाँकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं और ऐसे में यह सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है।

बसपा अध्यक्ष ने कहा कि, लोकसभा चुनाव को लेकर वह यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में, विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति-पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ 'अकेले' लड़ेगी। इन्हीं के बलबूते पर ही बसपा ने 2007 में यूपी में अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर, हमारी पार्टी लोकसभा के यह आमचुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूँजीवादी, संकीर्ण व साम्प्रदायिक सोच रखने वाली सभी पार्टियों से अपनी दूरी भी बनाकर रखेगी। अर्थात् पार्टी किसी भी गठबन्धन व पार्टी के साथ मिलकर यह चुनाव नहीं लड़ेगी।

मायावती ने कहा कि, बसपा गठबन्धन करके चुनाव लड़ने में बसपा का वोट तो गठबन्धन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपरकास्ट समाज का वोट, बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और इसका उदाहरण यह है कि यूपी में 1993 में हुये विधानसभा के आमचुनाव सपा से गठबन्धन करके लड़ने से बसपा केवल 67 सीटें ही जीतकर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुँचा था।

उन्होंने कहा, हाल ही में विपक्ष के इण्डिया गठबन्धन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत बसपा के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घन्टों के अन्दर उनके प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है।

मायावती ने कहा कि, पिछले महीने पार्टी की आल इण्डिया की बैठक में आम सहमति से आकाश आनन्द को उन्होने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था तो उसके बाद से बीच-बीच में मीडिया में फर्जी खबर प्रचारित की जा रही है कि बसपा प्रमुख जल्दी ही राजनीति से सन्यास लेने वाली है जिसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है, जबकि उनकी जिन्दगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा।

पीड़ित व्यक्ति की ग्राम पंचायत पर सुनवाई होनी चाहिये-मुख्यमंत्री शर्मा

- **भजन लाल शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि, लोगों को सुनवाई के लिये जिला मुख्यालय और राजधानी आने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।**
- **मुख्यमंत्री भजन लाल ने बांसवाड़ा की यात्रा में सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजना बनाने के निर्देश दिये।**

बांसवाड़ा, 15 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोगों को परिवेदनाओं के लिए जिला मुख्यालय और राजधानी तक नहीं आना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित जनसुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू "विकसित भारत संकल्प यात्रा" योजनाओं से वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य में एक भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे, यह हम सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार सबके साथ और सबके विश्वास से प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में अहम निर्णय ले रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और फैसलों को धरातल पर उतारकर पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने में प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। शर्मा ने सोमवार को बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने संभाग में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रभावी निगरानी के भी निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। हमने सरकार बनते ही पेपरलीक, गैंगस्टर और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष निर्णय लिए, जिनका असर दिखने लगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां की प्रगति के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई जायेगी। शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। शर्मा ने राजमार्गों एवं रेल लाईन से संबंधित मुआवजा प्रदान करने के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के लिए बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने संभाग में बिजली, पानी, सड़क व चिकित्सा आदि सुविधाओं की भी बिन्दूवार समीक्षा की। बैठक में संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन ने संभाग और तीनों जिलों के जिला कलक्टर ने जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा और विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राउमावि तलवाड़ा प्रांगण में लगे शिविर का अवलोकन किया। बाद में यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वागड़ को समृद्ध बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अंतिम छोर पर जरुरतमंद पात्र को चिह्नित कर लाभान्वित करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद कनकमल कटारा, विधायक कैलाश मीणा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, लाभचन्द पटेल, पुलिस महानिरीक्षक एस. परिमाला, बांसवाड़ा जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, डूंगरपुर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह, प्रतापगढ़ जिला कलक्टर अंजली राजोरिया, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिजीत सिंह बांसवाड़ा, अमित कुमार प्रतापगढ़ एवं कुन्दन कंवरिया डूंगरपुर सहित जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कॉलोनी का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एकलपीठ में जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि, कॉलोनी के गेट दिन में भी बंद रहते हैं और इससे कॉलोनी के दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

नगर निगम की ओर से विकास समितियों द्वारा अवैध तरीके से बंद रखे इन गेटों को खुलवाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि इससे व्यापक तौर पर आमजन प्रभावित है। जनहित याचिका में कहा गया कि, मूर्तिकला कॉलोनी की विकास समिति की ओर से कॉलोनी के गेट बंद रखे जाते हैं।

याचिकाकर्ता की पत्नी को हार्ट अटैक आने पर भी गेट नहीं खोला गया और उसे लंबा चक्कर लगाकर अस्पताल जाना पड़ा। इसके अलावा अन्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

इसकी सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

यू.पी. कांग्रेस के नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काल्पनिक चरित्र बताने वाले लोग अब जागृत हो रहे हैं। उन्होंने सच्ची राह पर चलना शुरु कर दिया है और अब उन्हें अपने अन्त:करण को भी शुद्ध कर लेना चाहिए।"

सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद राय व कांग्रेस के अन्य नेता हनुमानगढ़ी और नए भव्य राममंदिर भी गए।

22 जनवरी को हो रही प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेताओं के भाग ना लेने के बारे में पूछने पर राय ने कहा कि, मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर वे तीर्थ स्थल आए हैं।

राय ने पत्रकारों से कहा कि "क्या भगवान राम की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। हम मकर संक्रांति के महत्वपूर्ण शुभ अवसर पर भगवान की भक्ति करने आए हैं।

उन्होंने बाद में बताया, "हमने देश की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की।"

राय ने अयोध्या यात्रा की घोषणा, कांग्रेस के इस बयान के पहले ही कर दी थी कि, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नामंजूर कर दिया है। कांग्रेस के बयान में आरोप लगाया गया था कि, भाजपा चुनावी फायदे के लिए राममंदिर को एक "राजनीतिक प्रोजेक्ट" बना रही है।

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता उमा शंकर पाण्डे ने बताया कि राय, यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा मोना के साथ लखनऊ से सड़क मार्ग से सुबह अयोध्या पहुंचे।

कांग्रेस के सीनियर नेता दीपेन्दर सिंह हूडा अलग से अयोध्या पहुंचे। हूडा ने कहा कि "भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारा मानना है कि, भगवान राम सभी के हैं और हर व्यक्ति के भीतर विराजमान हैं। मैं पहली बार अयोध्या नहीं आया हूँ। रामलला की पूजा-आराधना के लिए एक वर्ष पहले भी मैं यहां आया था।"

अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद

जालंधर, 15 जनवरी। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) और पंजाब पुलिस ने सोमवार को राज्य के अमृतसर जिले के गांव भरोपाल से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया।

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि, दोपहर के समय, ड्रोन की उपस्थिति के संबंध में बीएसएफ से विशेष सूचना पर, बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा जिला अमृतसर के गांव भरोपाल के बाहरी इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान पार्टी ने एक चीन निर्मित क्वाडकॉप्टर (मॉडल - डीजेआई मविक 3 क्लासिक) ड्रोन बरामद किया।

न राम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने आज घोषणा की कि, वह आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी।

यह भी अब तक स्पष्ट नहीं है कि, क्या राहुल गाँधी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अखिलेश, राहुल गाँधी को पसंद नहीं करते।

राहुल के लिए अब आधारभूत बात यही है कि, "ना माया मिली ना राम।"

चुनाव से पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आई.आर. दर्ज की। सांसद हेगड़े ने शनिवार को उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कथित रूप से कहा था कि, कर्नाटक की भक्तल मस्जिद का उसी प्रकार विध्वंस किया जाएगा जैसा कि, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद का किया गया था।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि, "बाबरी मस्जिद की भांति भक्तल मस्जिद का विध्वंस भी सुनिश्चित है। यह निर्णय अनंत कुमार का नहीं बल्कि हिंदू समाज का है।" एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि, स्पष्ट रूप से इस बयान का मकसद दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करना और राजनीतिक लाभ उठाना है। भाजपा हिंदुत्व मुद्दे का अधिकाधिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस नेताओं के धर्मनिरपेक्ष विचारों को बकवास बताती है और उन्हें ऐसे लोगों के रूप में चित्रित करती है जो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कोई भी बयान आलोचना योग्य माना जाता है, यह आगामी लोकसभा चुनावों की भाजपा की समग्र रणनीति का एक हिस्सा है।

हेगड़े ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर तीखे शाब्दिक प्रहार किए। सिद्धारमैया ने कहा था कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का कोई आमंत्रण नहीं मिला। हेगड़े ने मुख्यमंत्री के इस कथन को लेकर भी उनकी भारी आलोचना की कि, उन्हें चाहे आमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन वह राम मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं लेंगे।

पुलिस कार्रवाई के अतिरिक्त, कांग्रेस ने भी भाजपा के प्रहारों का मुकाबला करने वाली अपनी रणनीति के पर्याप्त संकेत दिए। पिछले कुछ वर्षों के विपरीत कांग्रेस अब आक्रामक मुद्रा में आकर कानूनी कार्यवाही तक कर देती है। अधिकारिक रूप से, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर इस बार भाजपा सांसद के खिलाफ बैंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवायी और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की। कांग्रेस की शिकायत में कहा गया कि, "अनंत कुमार हेगड़े ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की निम्न स्तरीय आलोचना की है और खुले तौर पर यह भी कहा है कि, राज्य की मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए। राज्य में साम्प्रदायिक दंगे कराने का उनका इरादा जग जाहिर हो चुका है। उनका इरादा कानून-व्यवस्था के लिए एक चुनौती है।"

प. बंगाल में पी.डी.एस. घोटाले में ई.डी. ने की छापेमारी

- **टी.एम.सी. नेता शंकर आघा ने विदेशी मुद्रा कार्यालय तथा उसके चार्टर्ड अकाउन्टेंट के कार्यालय पर भी छापा मारा गया।**

कोलकाता, 15 जनवरी। पश्चिम बंगाल में कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस-राशन) घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां पूरे शहर में 3 से 4 स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आध्या के चौरंगी, कोलिन स्ट्रीट स्थित विदेशी मुद्रा कार्यालय और साल्ट लेक में अध्या के चार्टर्ड अकाउंटेंट अरविंद सिंह के कार्यालय पर छापेमारी की गई। उत्तर 24 परगना में बोंगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आध्या को ईडी ने लगभग 17 घंटे की पूछताछ और उनकी संपत्तियों पर तलाशी अभियान के बाद छह जनवरी को गिरफ्तार किया था।

सूत्रों ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कथित राशन घोटाले के धन के लेन-देन की जांच कर रही संघीय एजेंसी ने गिरफ्तारी के दिन ही अध्या के विदेशी मुद्रा कार्यालयों को सील कर दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही एजेंसी ने सील को तोड़ दिया और खोला तथा सशस्त्र केंद्रीय बलों की सहायता से तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी का मानना था कि निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना विदेशी मुद्रा के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपये का धन हस्तांतरित किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के विदेशी मुद्रा कार्यालयों में नवीनतम तलाशी अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि एजेंसी को जेल में बंद टीएमसी नेता को 20 जनवरी को एक विशेष अदालत में पेश करने की उम्मीद है। आध्या को गिरफ्तार खाद्य मंत्री ज्योतिर्मय मल्लिक के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। ईडी को संदेह है कि लगभग नौ हजार से दस हजार करोड़ रुपये सीधे या बांग्लादेश के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किये गये हैं।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर पीडीएस घोटाले की जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर विभिन्न निजी व्यक्तियों का पीडीएस राशन पर अनधिकृत कब्जा पाया गया और वे धान की फर्जी खरीद में शामिल पाये गये।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा कहा कि ईडी की जांच के दौरान, यह पता चला है कि अपराध की आय विभिन्न तरीकों को अपनाकर पैदा की गयी।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

- **महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे तथा अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को अध्यक्ष नार्वेकर ने 10 जनवरी को खारिज कर दिया था।**
- **सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार नार्वेकर को जल्दी फैसला देने के लिए कहा था।**

नयी दिल्ली, 15 जनवरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट (यूबीटी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

शीर्ष अदालत ने अयोग्यता पर फैसला लेने में देरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर से कई बार अपना फैसला शीघ्र देने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 10 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता, यूबीटी गुट के सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में कहा कि, निर्णयों की 'पूर्ण विकृति', इस तथ्य से स्पष्ट है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना, यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर भी विचार नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।

याचिका में कहा गया है कि, दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं। यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि, अध्यक्ष के फैसले में, इस निर्विवाद तथ्य की कोई सराहना नहीं है कि शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उनकी दलीलों और उनकी जिरह में की गई स्वीकारोक्ति कि वे 21 जून 2022 से भाजपा शासित राज्यों गुजरात और असम में थे।

याचिका में कहा गया है, "अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था।

भाजपा प्रदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना लगाया है। अब उनके स्थान पर वैश्य संगठन महामंत्री लगाए जाने की चर्चा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आने वाले समय में ओबीसी से लगाए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि करणपुर में मंत्री बनाए जाने के बाद भी जनता ने भाजपा के प्रत्याशी को नकार दिया। किसान व ओबीसी वर्ग में असंतोष, इस हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

बिस्किट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया और सामान भी वापस नहीं लिया। इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसे हर्जा-खर्चा सहित ज्यादा वसूली राशि लौटाने के लिए कहा है।

कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण करने में कोई प्रशासनिक अथवा कानूनी विलम्ब ना हो। एक आई.ए.एस. तो राज्य सरकार में सचिव व उससे ऊपर की वरियता का था, दूसरा केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव से ऊपर के पद का और तीसरा अयोध्या का जिला मजिस्ट्रेट था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र को ट्रस्ट की निर्माण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रोजैक्ट के लिए नृपेन्द्र मिश्र कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, उन्हें कैबिनेट रैंक के अनुसार प्रिंसिपल सैक्रेटरी के पद पर नियुक्ति दी गई।

निर्माण समिति के अध्यक्ष मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कैडर के अधिकारी हैं, वे भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनको उनकी सेवानिवृति के बाद मोदी ने वर्ष 2014 में अपने पास बुला लिया था। चूंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कानून, 1997, के प्रावधान अनुसार किसी पूर्व या निवर्तमान अध्यक्ष को सरकार में कोई पद नहीं दिया जा सकता अत: मोदी सरकार उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले तो अध्यादेश लाई और उसके बाद सेवा संबंधी कानून में ही संशोधन कर दिया।

कांग्रेस का कहना है कि, पूर्ण प्रयासों के बावजूद मंदिर अभी भी निर्माणाधीन ही है। मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सचिव चम्पत राय ने पिछले साल 16 दिसम्बर को एक न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि, यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा, क्योंकि गृर्भग्रह के साथ ही मूर्ति भी बनकर तैयार है, परन्तु निर्माणाधीन मंदिर के कार्य को पूर्ण होने में उद्घाटन के बाद भी दो वर्ष और लगेंगे।

राम मंदिर अयोध्या में लगभग तैयार है और उत्तर प्रदेश के इस शहर में अगले माह होने वाले मंदिर के शानदार उद्घाटन समारोह की तैयारी के चलते यहां आधारभूत सुविधाओं का कालाकल्प किया जा रहा है। राय ने यह भी कहा कि, भगवान राम की मूर्ति को उनके गृर्भग्रह में स्थापित करने के लिए होने वाले विशाल समारोह का साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त तीर्थ यात्री अयोध्या आएंगे। मंदिर के ऊपर का अभी भी काफी काम होना शेष है। मंदिर निर्माण का कार्य इस तिथि के बाद दो वर्ष चल सकता है।

कांग्रेसी नेता ने कहा कि, अगर राम मंदिर एक राजनीतिक परियोजना नहीं तो, ऐसा कोई भी मंदिर, जो अभी तक निर्माणाधीन चल रहा है और उसक निर्माण कार्य पूरा होना शेष है, उसके बारे में युजुर्वेद संहिता, मार्कण्डेय पुराण और हरवंश पुराण में कहा गया है कि, इस स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन समारोह नहीं किया जा सकता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त धर्माधिकारियों, जिनमें देश के चार शंकराचार्य भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने के लिए 22 जनवरी की तारीख को शुभ नहीं माना है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का इसके बारे में कहना है कि, उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अब साफतौर पर सवाल यह उठता है कि, उद्घाटन समारोह के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? प्रश्न का उत्तर किसी से छिपा नहीं है। इस बात को एक आम आदमी भी समझता है। यहां तक कि, इसके उद्देश्य के बारे में एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि, यदि अभी इस समय इस समारोह को आयोजित नहीं किया तो बाद में सत्तारूढ़ भाजपा लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुना नहीं सकेगी।

सत्तारूढ़ दल के रणनीतिकारों ने अपनी तोपें विशेष रूप से कांग्रेस पर दागी थीं जो कि वैचारिक रूप से आर.एस.एस.-भाजपा की विचारधारा का विरोध करती है। इस मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण सी.पी.एम. के महासचिव सीताराम येचुरी को भी प्रेषित किया गया है।

परन्तु लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया है कि, आमंत्रण पत्र सभी दलों को भेजा जा रहा है।

कांग्रेसी नेता ने कहा कि, सत्तारूढ़ भाजपा के इस तथ्य से भलीभांति वाकिफ हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो इस चुनावी परिदृश्य में भाजपा के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकती है इसी के चलते निमंत्रण पत्र सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन को दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, आमंत्रण ने कांग्रेस को गंभीर दुविधा में डाल दिया है। यदि इसने आमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब उसने पार्टी के धर्म निरपेक्ष होने के स्वरूप पर निश्चित रूप से दाग लगा लिया और उन काफी सारे लोगों को इस कदम से निराशा होगी जो देश के संविधान में आस्था रखते हैं।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को यह कह कर अस्वीकार करना कि, यह समारोह भाजपा और आर.एस.एस. की करतूत है, एक साहसिक कदम है, क्योंकि धर्म, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक निजी मामला है, कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट किया कि वह राम मंदिर का विरोध नहीं करती है, परन्तु मंदिर कब जाना है, यह हर व्यक्ति को अपना निर्णय करने का अधिकार है।

कांग्रेस के 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इंकार के बावजूद यह बात बिल्कुल साफ है कि, मंदिर उद्घाटन को लेकर बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय इस मुद्दे पर विभाजित है, क्योंकि इस कार्यक्रम का समय पूरी तरह राजनीतिक है और इसका भगवान राम में आस्था रखने से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्हें न्याय का सर्वोच्च समर्थक माना जाता है।

'अभिजीत मुहूर्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुहूर्त में होगा।

राय ने बताया कि, न्यूनतम तीन अधिवास चलन में हैं। अनुष्ठान में 121 आचार्य होंगे। इस अनुष्ठान के संयोजक गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ एवं प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी के होंगे।

उन्होंने बताया कि, रामजन्मभूमि मंदिर प्रांगण प्राण-प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए देश की सभी आध्यात्मिक धार्मिक मत, पंथ, संप्रदाय, उपासना पद्धितयों के सभी अखाड़ों के आचार्य, सभी परंपराओं के आचार्य, सभी सम्प्रदायों के आचार्य, 150 से अधिक परम्पराओं के सन्त, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, महंत, नागा साथ ही 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी तटवासी, द्वीपवासी जनजाती परंपराओं की उपस्थिति, भारत वर्ष के निकटवर्ती इतिहास में पहली बार हो रही है। यह अपने आप में विशिष्ट होगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908